RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-09
September-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i09.043

भूमण्डलीकरण और आज की शिक्षा व्यवस्था

प्रा. सुभद्रा कुमारी सिन्हा

सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, जे. ई . एस. महाविद्यालय जालना, महाराष्ट्र।

भूमण्डलीकरण हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में एक भूचाल की तरह आया जिसका कइयों ने स्वागत किया तो कईयों ने विरोध। भूमण्डलीकरण से एकमात्र प्रतिबद्धता बाजार को चुस्त–दुरूस्त बनाने के साथ है। इसके लिए यह सार्वभौमिक तौर पर सांस्कृतिक उत्पाद सहित सब कुछ को माल में बदल देता है। इस व्यवस्था में शिक्षा भी एक माल है। शिक्षा को आज उद्योग के रूप में चलाया जा रहा है और उद्योग की अवधारणा सीधे–सीधे मुनाफे से जुड़ी होती है।

शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में से एक है। संविधान में कहा गया है कि सबको समान शिक्षा मिले। इसे पूर्ण करने का दायित्व सरकार का है। आज शिक्षा की कमान निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इसका दुष्परिणाम इस रूप में सामने आ रहा है कि जैसे–जैसे निजी शिक्षण संस्थान की चमक–दमक, आकार–प्रकार बढ़ने लगी वैसे–वैसे सरकारी स्कूलों की दीवारें ढहने लगी, छतें चुने लगी, फर्श पर चींटियाँ रेंगने लगी। जबकि हमसे यह सच्चाई छिपी हुई नहीं है कि आज के जितने भी निजी शिक्षण संस्थान है वे सभी उपरी चमक–दमक से लबालब हैं। पूँजीपतियों द्वारा चलाए जा रहे निजी स्कूल लाखों को करोड़ों में तब्दील करने वाली मशीन है। ये सिर्फ मुनाफा कमाना जानती है। शिक्षा की गुणवत्ता से इसका कोई खास सरोकार नहीं होता। अनिल सदगोपाल का कहना है, " आजादी के चार–पाँच दशकों के बाद तक निजीकरण का मतलब बाजारीकरण नहीं था। निजी स्कूल व्यवस्थाएँ तब भी थीं लेकिन वे कभी भी यह नहीं सोचती थीं कि उन्हें शिक्षा से सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना है। लेकिन नवउदारीकरण लागू होने के बाद से निजीकरण, बाजारीकरण का पर्याय बन चुका है। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक पार्टी शिक्षा में पब्लिक–प्राइवेट–पार्टनशिल (पीपीपी) का विरोध नहीं कर रही है। शिक्षा के इस निजीकरण के जरिए समाज में गैर–बराबरी फैलायी जा रही है। निजी स्कूल संविधान में दर्ज समानता के दर्शन को कभी भी पनपने नहीं दे सकता है। "१

पब्लिक–प्राइवेट–पार्टनशिप के तहत जितने भी निजी शिक्षण संस्थान खोले गए उसका मुख्य उद्देश्य अर्थ प्राप्ति ही रहा है। ये संस्थान विद्यार्थियों के समक्ष इतने लोक लुभावन सपने परोसते हैं कि विद्यार्थी जाने अनजाने इसके कुचक्र में फँस जाते हैं। इन संस्थानों में विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना होता है। मानवी संवदेनाओं से इनका कोई खास सरोकार नहीं होता। इसलिए आज के युवा में इतनी संवेदनहीनता एवं स्वार्थीपन पाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप एवं भ्रष्टाचार भी शिक्षा के गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सरकारी संस्थानों की लचर शिक्षा–व्यवस्था का सीधे–सीधे फायदा निजी शिक्षण संस्थान उठाते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता न होकर व्यवसाय के रूप में चलाना है। फलस्वरूप निजी संस्थान अपने तरीके से विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में नियम बनाकर मनमाने ढंग से फीस वसूलते हैं।

उदारीकरण ने शिक्षा जगत को अत्यधिक प्रभावित किया है। आज जिस तरह की आर्थिक नीतियाँ अपनाई जा रही है उससे समाज को विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नव उदारवाद के कारण सरकार लगातार शिक्षा से हाथ खींच रही है और उसे निजी हाथों में सौंप रही है। ये निजी संस्थान कम से कम निवेश में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की होड़ में लगी रहती है। पवन कुमार शर्मा अपने लेख भारतीय शिक्षाः अतीत, वर्तमान और भविष्य में लिखते हैं, "बाजार का तंत्र आज सरकारी तंत्र के साथ मिलकर शिक्षा की बाजार उन्मुखी नीतियों का ही पोषण करता है। अंग्रेजी शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है की उसने समाज के उपर बाजार को स्थापित कर दिया है।" २ इस तरह न केवल शिक्षा व्यवस्था तबाह हुई है बल्कि अब उच्च शिक्षा पाने का अधिकार सिर्फ उच्च और मध्यवर्ग के लिए ही रह गया है। गरीब छात्रों के लिए ऐसे संस्थान बज्र के आघात के समान है।

कुछ युवा–छात्र छात्राओं में ज्ञान प्राप्ति की अद्भूत शक्ति होती है उसमें आगे बढ़ने की असीम संभावनाएँ होती है लेकिन फिर भी वे अर्थ के अभाव में विकलांग बनकर रह जाते हैं। विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को आकर देने की उनकी इच्छा सपना बनकर रह जाती है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक साँठ–गाँठ के चलते बेईमान, नौकरशाह, नेताओं की मूर्ख संतान तक को विदेशी विश्वविद्यालयों से शिक्षा लेने में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। उदारीकरण की इस तानाशाही नीति ने भारत की गरीब युवा पीढ़ी को बेबस और लाचार बना दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालेयुवा आज भी सरकारी संस्थानों की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, वहीं शहरी सम्पन्न वर्ग निजी एवं विदेशी शिक्षण संस्थानों में जाने को उतावले रहते हैं, भले ही उनमें वह काबिलियत न हो।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

बाजारवाद एवं निजीकरण ने शिक्षा को व्यवस्था मे तब्दील कर दिया है। यदि इस प्रक्रिया से शोध एवं पठन–पाठन में सुधार आता है तो यह प्रक्रिया भी स्वागत योग्य होती। मगर स्थितियाँ यथावत हैं। प्रख्यात शिक्षाशास्त्री प्रणय कृष्ण का मानना है कि, "शिक्षा पर कुछ अभिजात्य वर्ग एवं पूँजीपतियों का आधिपत्य स्थापित हो रहा है। भूमण्डलीकरण पूँजी और मुक्त बाजार की चाकरी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को जोत देने की तैयारी पूरी की है। इसके लिए तर्क सब वहीं है जो नव उदारवादी व्यवस्था के पैराकार देते आए हैं। यानि शिक्षा में निवेश की जरूरत के मुताबिक सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। शिक्षा में निजी पूँजी और विदेश से प्रतियोगिता बढ़ेगी जिससे गुणवत्ता में सुधार होगा और चुनने के लिए विकल्प ज्यादा होंगे आदि। बड़ी पूँजी जैसे–जैसे शिक्षा पर अपना प्रभुत्व कायम करती चली जाएगी, जीवन मूल्यों, सामाजिक विस्तार, आलोचनात्मक चेतना हर दृष्टि से शिक्षा का क्षेत्र संकुचित होगा।"३

शिक्षा के निजीकरण का चक्र इतनी तेजी से चल रहा है कि विदेशी विश्वविद्यालयों तक को यहाँ स्थापित होने का रास्ता खुल गया है। आगामी कुछ वर्षों में देश की उच्च राजनीतिक पार्टियां भी शिक्षा के निजीकरण के सवाल पर चुप्पी साध लेती है। शिक्षा आज मुनाफा कमाने का एक माध्यम बन गया है शिक्षा के निजी हाथों में चले जाने से सभी के लिए समान शिक्षा यह एक जुमला भर रह गया। इस तरह से समाज में गैर बराबरी फैलायी जा रही है। संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकारों के बावजूद गरीबों के लिए अलग स्कूल तथा धनिकों के लिए अलग स्कूल है। अनिल सद्गोपाल अपने लेख, बाजार की दहलीज पर शिक्षा, में लिखते है, "संविधान के १५वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों को एक समान दर्जा देगा। संविधान के १५वें अनुच्छेद के उप–अनुच्छेद (१) में यह भी कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक से जाति, संस्कृति, धर्म या प्रदेश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इतना मजबूत संविधान होने के बावजूद भारतीय राज्य ने इस तरह की शिक्षा व्यवस्था खडी की है जिसमें गरीबों और अमीरों के लिए अलग–अलग स्कूलों की व्यवस्था संभव हो गयी है। भारत जैसे मुल्क जहाँ ८० फीसदी गरीब जनता है, वहाँ ५० रूपये का भी शुल्क लगाने का मतलब गैर–बराबरी की शिक्षा नीति को बढ़ावा देना होगा।"४

शिक्षा में विश्वस्तरीय कायाकल्प होगा। भूमण्डलीकरण के प्रभाव से शिक्षा में विश्वस्तरीय कायाकल्प तो होगा लेकिन क्या इसका फायदाउन आधी से अधिक आबादी को मिल पाएगी जिसे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा और मकान) की पूर्ति के लिए भी दिन–रात कोल्हू की बैल की तरह घिसना पड़ता है? उच्च शिक्षा की यह अवधारणा पूँजीपतियों के लिए ही लाभकारी है। यह सच है कि आगे जा शिक्षण संस्थान खुलेंगे वे लगभग सभी निजी संस्थानों के तर्ज पर चलाए जाएंगे। यानी उस में शिक्षा के विषय और शिक्षा हासिल करने की कीमत निजी संस्थानों जैसी होगी। उच्च शिक्षा के इस अवधारणा को हम भारतवासी तभी दिल से स्वागत कर पाते जब यह शिक्षा पूरी आबादी के जीवन स्तर को उंचा उठाती। ऐतराज सिर्फ इसलिए है कि यह सिर्फ एक खास वर्ग के लिए है।यह नवसाम्राज्यवाद का दौर है। अब वैश्विक आर्थिक संस्थाएँ और बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ एक के बाद एक क्षेत्र सभी को अपने कब्जे में लेती जा रही है। देश की सरकार इस नवसाम्राज्यवादी मुहिम में तत्पर सहयोगी बनी हुई है।

शिक्षा में व्याप्त निजीकरण की प्रवृत्ति ने कई तरह की जटिलताओं को जन्म दिया है जैसे असंतोष, अवसरों की कमी आदि। विकास की यह चमचमाती दुनिया उन्हीं लोगों के लिए है जो साधन सम्पन्न हैं। प्रेम सिंह अपने लेख, 'अब शिक्षा का बाजार' में लिखते हैं, "उदारीकरण–वैश्वीकरण की नीतियों ने अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा के क्षेत्र पर भी तेजी से आक्रमण करना शुरू कर दिया है। नतीजतन शिक्षा के स्वरूप और संचालन–प्रबन्धन के बारे में एक के बाद एक ऐसे सरकारी निर्णय लिए जा रहे हैं जिनसे न केवल शिक्षा पर निजीकरण का शिकंजा कसता जा रहा है, शिक्षा की परिभाषाएँ भी बदला जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में गौरतलब और चिन्ता का विषय यह है कि ये सारे निर्णय वैश्विक आर्थिक संस्थाओं के अधिकारियों के निर्देशों पर खुद सरकार, नौकरशाह और सरकार के पिट्ठू बुद्धिजीवी कर रहे हैं। हाल में विश्व बैंक ने शिक्षा के मद में कर्ज का धन देने से इसलिए इनकार कर दिया कि भारत ने शिक्षा के निजीकरण की अपेक्षित गति तय नहीं की हैं।"५

इस तरह का दबाब सरकार पर बनाया जाता रहा है। मैकाले का सपना पूर्णतः सच होते दिखाई दे रहा है। मैकाले ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह दावा किया था कि मैं ऐसी शिक्षा प्रणाली लाऊंगा जिसके तहत भारतीयों की एक बड़ी संख्याँ जन्म और शरीर से तो भारतीय होंगे किंतु अपने रहन सहन सोच में पूरी तरह अंग्रेज बन जाएँगे। इस के लिए उन्होंने उस समय के गवर्नर जनरल पर यह दबाव डाला कि स्कूलों में छठी कक्षा के बाद संस्कृत और अरबी के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य किया जाए तथा शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी ही हो। उसका यह सपना निर्धारित समय से पहले ही पूरा हो गया।

शिक्षा का उद्देश केवल विद्यार्थी को साक्षर एवं आत्मनिर्भर बनाना ही नहीं बल्कि सामाजिक विकास में उसे हिस्सेदार बनाना भी है। लेकिन यह संभव होगा कैसे? भूमण्डलीकरण के इस युग में तो मानविकि शिक्षा को हाशिए पर धकेल दिया गया है। आकड़े बताते हैं कि मानविकी और सामाजिक विषयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र गरीब तबके के होते हैं। इसलिए प्राइवेट शिक्षण संस्थानों तक न तो ऐसे छात्र पहुँच पाते हैं ओर न ही वहाँ ऐसी शिक्षा की पढ़ाई करायी जाती है। कारण स्पष्ट है कि इससे उसको आर्थिक लाभ नहीं है। या यूँ कहें कि मानविकी शिक्षा को खत्म करने

RRIJM 2015, All Rights Reserved

की सरकार और निजी संस्थान की एक साजिश है। क्योंकि सत्ता के विरुद्ध सवाल खड़ा करने की ताकत मानविकी विषयों में ही है। सामाजिक समरसता, सामाजिक भेद, साम्प्रदायिकता इन सबके प्रति मानविकी विषय अत्यंत संवेदनशील होते हैं। एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है। यह भूमण्डलीकरण का प्रभाव है कि ऐसे परम्परागत विषयों को हेय दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि शिक्षा के बाजार में ये बिकने योग्य नहीं है। रोजगारन्मुख शिक्षा के नाम पर बिकने लायक विषयों की भरमार खड़ी कर दी गयी है। गुणवत्ता की परवाह किए बगैर रोजगारन्मुख विषयों के प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं।

इसका दूसरा पहलू यह है कि उदारीकरण से शिक्षा को नुकसान ही पहुँचा है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सूचना आधारित संचार प्रणालियों ने ज्ञान को देश काल की सीमाओं से स्वतंत्र भी किया है। इंटरनेट ने तथ्य परक ज्ञान के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षण की परम्परागत प्रविधियों पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इसी वजह से कुछ परिवर्तन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

संदर्भ सूची :

1. समय से संवाद – ८, शिक्षा भरा पूरा अकाल, बाजार की दहलीज पर शिक्षा, अनिल सदगोपाल, सं. स्वतंत्र मिश्र, अनन्य प्रकाशन सं. २०१५, पृ. ७६
2. योजना, जनवरी २०१६, पवन कुमार शर्मा, भारतीय शिक्षा अतीत, वर्तमान और भविष्य सं. दीपिका कच्छल, नयी दिल्ली, पृ.सं. २२
3. भूमंडलीकरण, युवा जीवन एवं उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ, विपिन कुमार शर्मा, भारतीय शिक्षा, जनवरी २०१६ सं. राजरानी, श्वेता उप्पल, पृ. २०
4. समय से संवाद ८, शिक्षा भरा पूरा अकाल स्वतंत्र मिश्र (संपा.) अनन्य प्रकाशन, संस्करण–२०१५, पृ.स. ७६
5. उदारीकरण की तानाशाही, प्रेम सिंह, राजकमल प्रकाशन, सं. २००८, पृ. ८२

RRIJM 2015, All Rights Reserved